The ACHIEVERS IAS ACADEMY

ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

10/08/2023

+91 8434931877, +91 7250667974 www.achieversiaspatna.co.in

New Patliputra Colony, Road No. 4A, Near Tennis Court, Patna-13

THE HINDU National

शाह ने मणिपुर में शांति की अपील की, सीएम बीरेन का समर्थन किया

लोकसभा में मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई.बुधवार को गृहमंत्री अमितशाह ने मणिपुर पर सरकार का पक्षरखा. दो घंटे के भाषण में उन्होंने कई संबंधित मुद्दों को छुआ

हिंसा काकारण

उन्होंने हिंसा की निंदा की. उन्होंने इसकी वजह म्यांमार में सत्ता पर सैन्य कब्ज़ा होने के बाद कु की ज़ो मीजन जाति का वहां से पलायन करना बताया. और उनके लिए मणिपुर उच्च न्यायालय का निर्णय तात्कालिक कारण था। उन्होंने बताया कि हिंसा में अब तक कुल 152 लोगों की मौत हो चुकी है.

सीएमबीरेन सिंहका बचावकिया

एमिफ की मांग है कि मणिपुर के सीएम को हटाया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। श्री अमित शाह ने बताया कि जब मुख्यमंत्री "सहयोग" नहीं कर रहे हों तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, लेकिन मणिपुर मामले में मुख्यमंत्री पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं।

"हमने राज्य के लिए नया मुख्य सचिव भेजा, डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार बदले और सीएम ने इसमें सहयोग किया।"

ऐसीघटनाओं काराजनीतिकरण करनेके बारेमें

उन्होंने बताया कि यह शर्म की बात है कि मणिपुर जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इससे भी बदतर यह है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति होती है। उन्होंने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का हवाला दिया, जिसमें शुरू में उन्होंने हेलीकॉप्टर लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ घंटों तक हंगामा करने के बाद वह हेलीकॉप्टर ले गए।

मणिपुरमें समुदायोंसे अपील

उन्होंने मणिपुर में दोनों समुदायों से हिंसा छोड़कर एक-दूसरे और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की।

केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बिना कोई पुलिस ऑपरेशन नहीं, शास ने कुकी-ज़ो टीम को आश्वासन दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुकी ज़ो समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक की

वार्ता में इंडिजिनस ट्राइबल लिबरेशन फोरम (आईटीएलएफ) के सदस्यों ने भाग लिया। निम्नलिखित परिणाम वहाँ थे

गृह मंत्री अमित शाह ने कुकी ज़ो नेताओं से राजनीतिक वार्ता से पहले क्षेत्र में शांति बहाल करने को कहा

उन्होंने आश्वासन दिया कि मणिपुर पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बिना पहाड़ी इलाकों में अभियान नहीं चलाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाली सभी चौकियों पर प्रतिनिधिमंडल की नजर असम फाइलों पर होगी।

आईटीएलएफ ने सरकार के समक्ष 10 मांगें रखीं, जिनमें बफर जोन में अधिक बलों की तैनाती, चुराचांदपुर में लांबा जांच आयोग का कार्यालय स्थापित करना शामिल है।

एचएम ने कुकी ज़ो समुदाय से एस बोलिजांग गांव के 35 सदस्यों को दफनाने की अपनी योजना को स्थगित करने के लिए कहा, जिसकी योजना शुरुआत में 3 अगस्त को बनाई गई थी। एचएम ने दफन स्थल में बदलाव के लिए कहा क्योंकि यह संघर्ष क्षेत्र में आता है। इससे पहले मणिपुर उच्च न्यायालय ने बोजांग गांव में 35 सदस्यों को दफनाने की कुकी ज़ो योजना को प्रतिबंधित कर दिया था, स्टेन्हास बीबेन को अगली सुनवाई तक 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।

नाम न छापने की शर्त पर एक सदस्य ने कहा कि जब भी उन्होंने राजनीतिक समाधान पर जोर दिया, एचएम ने पहले शांति का आह्वान किया। कुकी ज़ो नेता अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं।

स्वदेशी वेब ब्राउज़र विकसित करें नकद पुरस्कार प्राप्त करें

इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने बुधवार को "दुनिया के लिए" एक स्वदेशी वेब ब्राउज़र बनाने में मदद करने वाले डेवलपर्स के लिए ₹3.4 करोड़ के नकद पुरस्कार की घोषणा की, लेकिन ब्राउज़र विचारों को प्रमाणन प्राधिकरण (सीसीए) के नियंत्रक पर भरोसा करना होगा। भारतीय सरकार प्राधिकरण और सुरक्षा सॉकेट लेयर सर्फ़िकेट (एसएसएल)।

एसएसएल और सीसीए जैसे प्रमाणपत्र सत्यापित करते हैं कि वेबसाइट खुद को एन्क्रिप्ट करती है और इस प्रकार विज़िट किए गए लिंक की सुरक्षा के बारे में बताती है। यह वायरस के हमले से बचाता है। एसएसएल प्रमाणपत्र आमतौर पर Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox जैसे ब्राउज़र उपयोग करते हैं। सीसीए भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है और आमतौर पर कोई भी कंपनी इसका उपयोग नहीं करती है। सरकार विदेशी वेब ब्राउज़र और सर्टिफिकेट दोनों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है।

रो खन्ना भारत यात्रा के दौरान मानवाधिकार का मुद्दा उठाएंगे: अमेरिकी नागरिक अधिकार समूह

भारतीय अमेरिकी अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत में अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रो खन्ना ने बताया है कि भारत में मानवाधिकारों पर चर्चा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने भारतीय अमेरिकी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल लाल किले में पीएम के 15 अगस्त के भाषण में भाग लेगा। वह अपनी यात्रा पर पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। चर्चा किए जाने वाले अन्य मुद्दों में डीकार्बनाइजेशन, जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण और आर्थिक सहयोग शामिल होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू-कश्मीर संविधान ने भारत संघ की कार्यकारी शक्तियों को सीमित कर दिया है

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। बुधवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि किसी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के दायरे में लाने की कोशिश क्यों नहीं की।

"1957 के बाद, न तो सरकार और न ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा और न ही देश के बाकी हिस्सों में राजनीतिक प्रतिष्ठान ने जम्मू-कश्मीर को स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के दायरे में लाने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने के बारे में सोचा।" उन्होंने सवाल किया, "क्या किसी अन्य संविधान को मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना आवश्यक था? क्या संसद की शक्ति पर बंधन लगाना आवश्यक था।"

World

चुनाव के लिए मंच तैयार करने के लिए पाकिस्तान की संसद को भंग किया जाएगा

पीएम शाहबाज शरीफ ने कहा कि वह राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सलाह देंगे.संसद का पांचसाल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है।चुनाव में देरी हो सकती है क्योंकि चुनाव निकाय जनगणना के बाद नए निर्वाचन क्षेत्र के गठन में व्यस्त है।

2018 के चुनावों में इमरान खान की पार्टी पीएमएल विजेता बनकर उभरी थी।

चीन की अर्थव्यवस्था अपस्फीति की ओर अग्रसर है

चीन के राष्ट्रीय स्टेटिक्स ब्यूरो (एनबीएस) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों में कहा गया है कि चीन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक साल दर साल जुलाई में .3% गिर गया। उत्पादन मूल्य सूचकांक (पीपीआई) में लगातार 10वीं बार 4.4% की गिरावट आई। चीन सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य 3% है।

अपस्फीति वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट की स्थिति है, यह मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत है। अपस्फीति के पीछे का कारण मांग में गिरावट बताया जाता है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में विकास के बहुत अलग-अलग प्रक्षेपवक्र हैं।

रानिल ने सदन को बताया, "पुलिसिंग शक्तियों के बिना 13ए पर ध्यान केंद्रित करना व्यावहारिक" है।

श्रीलमकम के अध्यक्ष ने सोमवार को संसद में कहा कि 13ए को इसके तहत पुलिस को अधिकार दिए बिना लागू करना बेहतर होगा.

13 ए में प्रांतीय चुनावों और केंद्र द्वारा प्रांतों के साथ सत्ता साझा करने की बात कही गई है। पुलिस प्रांतीय सरकार के अधीन आ जाएगी। श्री रानिल ने बताया कि बेहतर होगा कि विवादास्पद मुद्दों को किनारे रखकर प्रांतीय सत्ता साझेदारी पर समझौते के साथ आगे बढ़ें। श्रीलंकाई संसद में तमिल सांसदों के एक समूह तमिल नेशनल अलायंस (टीएनए) ने राष्ट्रपति के प्रस्ताव को "स्पष्ट रूप से खारिज" कर दिया।

श्रीलंका में पिछले 5 वर्षों से कोई प्रांतीय सरकार नहीं है। हालाँकि पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं लेकिन सत्ता का वितरण उस तरह नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। द्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में रहने वाले तमिल प्रांतीय चुनाव की मांग कर रहे हैं।

ब्रिटेन के मतदाता डेटा को "शत्रुतापूर्ण अभिनेताओं" द्वारा हैक किया गया: मतदान निकाय

यूके चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि अगस्त 2021 से मतदाताओं का डेटा हैक कर लिया गया है। हालाँकि अधिकारियों को अक्टूबर 2022 में ही उल्लंघन के बारे में पता चला। तब तक हैकर्स ने सभी डेटा तक पहुँच बना ली थी। लगभग 40 मिलियन लोगों के डेटा से समझौता किया गया है। कई ऐसे भारतीय भी हैं जिनके पास आम चुनाव में वोटिंग का अधिकार है, उनका डेटा भी इसके अंतर्गत आता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसके बारे में किसी संदिग्ध के बारे में बात नहीं की गई है. कई वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है.

अमेज़ॅन राष्ट्र संयुक्त रूप से वनों की कटाई से लड़ेंगे

आठ दक्षिण अमेरिकी देशों ने मंगलवार को अमेज़ॅन वर्षावन में वनों की कटाई से लड़ने के लिए एक गठबंधन शुरू करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें वनों की कटाई को "बिना वापसी के बिंदु" तक पहुंचने से रोकने की कसम खाई गई। बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला ने अमेज़ॅन नदी के मुहाने बेलेमनाट में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता सतत विकास, वनों की कटाई और इसे बढ़ावा देने वाले संगठित अपराध को समाप्त करने के लिए एक रोडमैप की बात करता है।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

Niger